श्याम लाल शर्मा और अन्य

बनाम

भारत संघ

नवंबर 8/26, 1985

[पी. एन. भगवती, सी. जे., वी. डी. तुलजापुरकर, आर. एस. पाठक, डी. पी. मैडन और एम. पी. ठाकर, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 310(1) और 311(2)(बी)-शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है- व्यक्तिगत संतुष्टि पर नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से- श्रमिकों को आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करने और प्रयास करने का अधिकार है- संविधान निर्माताओं ने किसी श्रमिक की हड़ताल को तोड़ने के लिए प्रावधान नहीं बनाए।

याचिकाकर्ता, जो रेलवे कर्मचारी थे, उन्हें हड़ताल पर रहने, रेलवे सेवाओं को ठप्प करने, निष्ठावान कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मारपीट करने और डराने-धमकाने आदि के लिए बिना किसी जांच के या तो बर्खास्त कर दिया गया या सेवा से हटा दिया गया। बर्खास्तगी या निष्कासन के आदेश इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए, अन्य

रिट याचिकाओं और सिविल अपीलों के साथ सुनवाई की गई और 11 जुलाई, 1985 के फैसले से खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने उक्त फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया कि बहस के दौरान, पक्ष इस धारणा पर आगे बढ़े थे कि न्यायालय केवल तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किए गए सात प्रश्नों और व्यक्तिगत याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगा, और या तो इस न्यायालय की खंडपीठो द्वारा या संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाया जाएगा, कि पक्षों ने केवल उन सामान्य प्रश्नों पर अपने तर्क और प्रस्तुतियाँ संबोधित कीं, कि लिखित प्रस्तुतियाँ केवल स्थानांतरण मामले संख्या 55 /1982 में सभी रेलवे मामलों में की गई थीं कि किसी भी याचिकाकर्ता को अपने मामलों पर योग्यता के आधार पर बहस करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, कि समीक्षाधीन निर्णय ने सभी स्थानांतरित मामलों को खारिज कर दिया और इस प्रकार इन सभी याचिकाओं का निर्णय भी योग्यता के आधार पर किया गया, कि इससे उनके मामलो को गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है और इसलिए, न्याय के हित में, योग्यता के आधार पर याचिकाओं पर बहस करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।

समीक्षा याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

पी.एन. भगवती, सी.जे., वी.डी. तुलजापुरकर, आर.एस. पाठक और डी.पी. मदान न्यायाधिपतिगण के द्वारा।

समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं क्योंकि आग्रह किये गये आधारों में कोई दम नहीं है।

एम.पी. ठक्कर, न्यायाधिपति द्वारा- असहमति

I. समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने और दूसरे पक्ष को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अच्छा आधार है। [904 ई]

2. आधार में दम है क्योंकि समीक्षा याचिकाओं पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा कथनों का खंडन नहीं किया गया है। बहुमत के फैसले में यह भी नहीं कहा गया है कि प्रकथन तथ्यात्मक रूप से असत्य हैं। [901 डी-ई]

3. नरपत सिंह के मामले पर उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर बहस नहीं की गई, यह सही है। जब तक समीक्षा याचिका के पैरा 9 में दिए गए तथ्यात्मक कथनों को असत्य नहीं दिखाया जाता है, इन्हें इस आधार पर विवादित आदेश को ख़राब करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि यह दिमाग के गैर-प्रयोग को प्रकट करता है और 'कोई सबूत नहीं' पर बनाया गया है। [902 सी]

4. बहुमत के फैसले में कानून के प्रस्ताव को प्रतिपादित किया गया है कि अनुच्छेद 310(1) के तहत आनंद का प्रयोग अधिनियम में निर्दिष्ट प्राधिकारी या अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों द्वारा भी किया जा सकता है। [902 डी-ई]

5. अनुच्छेद 310(1) के तहत शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा भी किया जा सकता है, अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि पर नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर। क्या उसी शक्ति का प्रयोग एक डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर या कोई अन्य निचला अधिकारी अपने दम पर कर सकता है, उसके मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह से काम करने का कोई सवाल ही नहीं है? क्या डी.एम.ई. जो राष्ट्रपति के नाम पर भी कार्य नहीं करता, राष्ट्रपति के लिए सरोगेट है? यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है जिसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य से इसकी जांच नहीं की गई है, हालांकि इस बिंदु पर बहस हुई थी: [903 बी-डी]

6. क्या यह दो स्वर में बोलने के समान नहीं होगा कि किसी कामगार को दी जाने वाली सजा की मात्रा के संबंध में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही अब तक घोषित कानून यह मांग करता है कि एक काला बाजारी भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना विपणनकर्ता को काली सूची में नहीं डाला

जा सकता? क्या राष्ट्र के लिए 'पसीना' बहाने वाला एक कार्यकर्ता, राष्ट्र का 'खून बहाने' वाले कालाबाजारी करने वाले के समान व्यवहार का हकदार नहीं है? [903 डी-ई]

7. श्रमिकों को निश्चित रूप से उस देश में आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करने और प्रयास करने का अधिकार है, जिसके संविधान की प्रस्तावना में इसे "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित किया गया है। इस तरह के संघर्ष के दौरान हड़ताल पर जाने को देश को फिरौती के लिए मजबूर करने और तिरस्कृत करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। न ही उन्हें एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अपने आर्थिक संकट और दुर्दशा को दूर करने के प्रयास के लिए निजी लाभ चाहने वालों के रूप में निंदा की जा सकती है और उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि श्रमिकों द्वारा देशव्यापी आम हड़ताल होती है तो किसी भी श्रमिक के मामले में जांच करना "उचित रूप से व्यावहारिक" नहीं है। [904 बी-904 डी]

8. अनुच्छेद 311(2)(बी) निश्चित रूप से सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए श्रमिकों की मांगों के समर्थन में बुलाई गई हड़ताल को 'तोड़ने' के लिए संस्थापक पिताओं द्वारा डिजाइन नहीं किया गया था। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए। [904 डी]

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: समीक्षा याचिका संख्या 571-586 और 586 ए/1985

स्थानांतरण मामले संख्या 52-68/1982 में

सर्कुलेशन द्वारा

द्वारा न्यायालय का आदेश दिया गया।

आदेश

हमने समीक्षा याचिका में बताए गए आधारों पर विचार किया है और चूंकि हमें उनमें कोई तथ्य नहीं मिला, इसलिए समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।

ठक्कर, न्यायाधिपति द्वारा, हालांकि बहुमत से असहमत होना स्वीकार्य नहीं है, मेरी अंतरात्मा आदेश देती है, और मेरे कर्तव्य की भावना यह मांग करती है कि मुझे असहमत होना चाहिए। समीक्षा याचिकाओं को इस टिप्पणी के साथ खारिज करने के प्रस्तावित आदेश से असहमत हूं कि "हमें उनमें कोई तथ्य नहीं मिला"। याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा आग्रह किए गए आधारों को साबित करने के लिए अदालत में सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना।

2. याचिकाओं में आग्रह किए गए आधारों में से एक, ग्राउंड नंबर 8 है:

"8. बहस के दौरान पक्षकार इस धारणा पर आगे बढ़े थे कि माननीय न्यायालय केवल तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए 7 प्रश्नों पर निर्णय करेगा और व्यक्तिगत याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर या तो इस माननीय न्यायालय की खंडपीठों द्वारा या संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाया जाएगा। यह इस धारणा पर था कि पक्षकारो ने केवल उन सामान्य प्रश्नों पर अपने तर्क और प्रस्तुतियाँ दीं। यही कारण है कि लिखित प्रस्तुतियाँ केवल टी.सी. संख्या 55/1982 में ही की गईं सभी रेलवे मामलों के बीच । किसी भी याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर अपने मामले पर बहस करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। समीक्षाधीन निर्णय ने सभी स्थानांतरित मामलों को खारिज कर दिया और इस प्रकार इन सभी याचिकाओं का निर्णय भी गुण-दोष के आधार पर किया गया। इसलिए, यह आवश्यक है कि न्याय के हित में, याचिकाकर्ता को योग्यता के आधार पर अपनी याचिकाओं पर बहस करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। इससे उनके मामलों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यह यहां दिए गए कुछ मामलों के संदर्भ के तथ्यों से स्पष्ट है।"

यह कहना संभव नहीं है कि इस आधार में कोई दम नहीं है क्योंकि समीक्षा याचिकाओं पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा कथनों का खंडन नहीं किया गया है। इसलिए बहुमत के फैसले में यह भी नहीं कहा गया है कि यह कथन तथ्यात्मक रूप से असत्य है। समीक्षा याचिका संख्या 571 से 586 ए /1985 में आधार नंबर 9 का संदर्भ दिया जा सकता है जो इस प्रकार है: -

> "9. यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता श्री नरपत सिंह को उपरोक्त पैरा 3 में पुनरुत्पादित के समान कार्यालय आदेश दिया गया था और उन पर 3.2.1981 से काम बंद करने और अपने कर्तव्य के स्थान से गायब रहने का आरोप लगाया गया था और निष्ठावान कर्मचारियों को ड्यूटी पर न आने के लिए डराने-धमकाने और दबाव डालने के लिए।
>
> तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता नरपत सिंह अस्थमा का मरीज है और दिसंबर 1980 से 1.2.1981 के बीच आउटडोर मरीज के रूप में रेलवे मेडिकल अथॉरिटीज से इलाज करा रहा था। 2.2.1981 को जब वह शेड-मैन के रूप में डीएसएल/शेड बीजीकेटी में 6 घंटे से 14 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी पर थे, तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी

और वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गए। उन्होंने 2.2.1981 को जीएफओ/डीएसएल बीजीकेटी से सिक मेमो जी/92 प्राप्त किया और ड्यूटी छोड़ते समय याचिकाकर्ता द्वारा उचित प्रभार सौंप दिया गया। उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी गई और 27 दिनों के लिए 2.2.1981 का बीमार प्रमाणपत्र संख्या 62 प्रस्तुत किया गया।

इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को 3.2.1981 से काम से अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है, जबकि उसने 2.2.1981 को जी-92 प्राप्त किया था और अपना बीमार प्रमाण पत्र भेजा था और आवश्यकतानुसार बीमार होने की सूचना देने की सभी औपचारिकताओं का नियमों के तहत पालन किया था। यदि मामलों में योग्यता के आधार पर बहस की गई होती, तो याचिकाकर्ता नरपत सिंह ने माननीय न्यायालय को दिखाया होता कि अनधिकृत अनुपस्थिति पर उसके साथ कैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है और बर्खास्तगी आदेश एक यांत्रिक तरीके से दुर्भावनापूर्ण जारी किया गया है और कायम नहीं रखा जा सकता।"

यह बात सही है कि नरपत सिंह के मामले में उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर बहस नहीं की गई। जब तक पैरा 9 में दिए गए तथ्यात्मक कथनों को असत्य नहीं दिखाया जाता है, इन्हें इस आधार पर विवादित आदेश को ख़राब करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि यह दिमाग के गैर-प्रयोग को प्रकट करता है और 'कोई सबूत नहीं' पर बनाया गया है। यह समीक्षा याचिका पर विचार करने और अदालत में सुनवाई के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का एक अच्छा आधार है।

3. बहुमत के फैसले में [1985] 3 एससीसी 398 (451) पैराग्राफ 59 में कानून के प्रस्ताव को प्रतिपादित किया गया है कि अनुच्छेद 310(1) के तहत आनंद का प्रयोग अधिनियम में निर्दिष्ट प्राधिकारी या अनुच्छेद 309 (परंतुक) के तहत बनाए गए नियमों द्वारा नीचे उद्धृत परिच्छेद में भी किया जा सकता है,:-

> "इस प्रकार, हालांकि अनुच्छेद 310(1) के तहत एक सरकारी कर्मचारी का कार्यकाल राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है, ऐसी इच्छा का प्रयोग या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, जो उनकी सहायता से कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह या अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए अधिनियमों में या ऐसे अधिनियमों के

तहत बनाए गए नियमों में या अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों में और अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (सी) के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सलाह, जांच को राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि पर नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से प्राप्त उनकी संतुष्टि पर समाप्त किया जाना है..." (जोर दिया गया)

इस संदर्भ में निम्नलिखित जैसे गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठते हैं: जब संविधान उच्चतम कार्यकारी कार्यालय के पदधारियों पर आनंद के प्रयोग के संबंध में शक्तियों का सलाहपूर्वक निवेश करता है, तो क्या इन शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य अधिकारी, जैसे डिवीजनल मकैकेनिकल इंजीनियर (डीएमई) द्वारा किया जा सकता है। व्याख्या की प्रक्रिया (संशोधन नहीं) द्वारा क्या यह समझा जा सकता है कि अनुच्छेद 310 (1) के आधार पर राष्ट्रपति जो कर सकते हैं, रेलवे का डीएमई उसी अनुच्छेद के आधार पर कर सकता है? यह वस्तुतः "या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा..." शब्द जोड़कर अनुच्छेद 310 (1) में संशोधन करने जैसा होगा। यानी संविधान में एक अनुच्छेद को दोबारा लिखना. क्या यह अनुमति योग्य है? इससे भी अधिक, अनुच्छेद 310 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा भी किया जा सकता है, अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि पर नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर। क्या उसी शक्ति का

प्रयोग डी.एम.ई. द्वारा किया जा सकता है? या कोई अन्य निचला पदाधिकारी अपने दम पर काम कर रहा है, तो उसके मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह से काम करने का कोई सवाल ही नहीं है? क्या डीएमई जो राष्ट्रपति के नाम पर भी कार्य नहीं करता, राष्ट्रपति के लिए सरोगेट कर सकता है? यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है जिसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन इस दृष्टिकोण से इसकी जांच नहीं की गई है, हालांकि इस बिंदु पर बहस हुई थी। यह समीक्षा याचिका पर विचार करने और अदालत में सुनवाई के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का एक और आधार है।

4. समीक्षा याचिका पर विचार करने का एक अन्य आधार यह है: क्या यह दो स्वरों में बोलने के समान नहीं होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि एक कामगार को दी जाने वाली सजा की मात्रा के संबंध में भी, भले ही अब तक घोषित कानून यह मांग करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना किसी कालाबाजारी करने वाले को भी काली सूची में नहीं डाला जा सकता है? क्या राष्ट्र के लिए 'पसीना' बहाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्र को 'खून बहाने' वाले कालाबाजारी करने वाले के समान व्यवहार का हकदार नहीं है?

5. समीक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रतिपादित सिद्धांत के संदर्भ में भी उठता है [1985] 3 एससीसी 398 (522, 523), पैराग्राफ 170, 173:-

> "हो सकता है कि रेलवे कर्मचारी सरकार पर अपनी मांगें पूरी करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से ये हड़तालें कर रहे हों। उनकी मांगें उनके निजी लाभ और उनके निजी हित में थीं। इन मांगों को मनवाने की कोशिश में उन्होंने अनकही कठिनाइयों का कारण बना और जनता की भलाई और सार्वजनिक हित तथा राष्ट्र की भलाई और हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
>
> ..... अखिल भारतीय हड़ताल के संदर्भ में, जहां बहुत बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था, रेलवे सेवाएं ठप हो गईं, वफादार कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला किया गया और उन्हें डराया गया, देश को फिरौती के लिए रखा गया, देश की अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, स्थिति को सामान्य करने के लिए त्वरित और तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया। इन परिस्थितियों

में, यह नहीं कहा जा सकता कि जांच उचित रूप से व्यावहारिक थी।"

श्रमिकों को निश्चित रूप से उस देश में आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करने और प्रयास करने का अधिकार है, जिसके संविधान की प्रस्तावना में इसे "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित किया गया है। इस तरह के संघर्ष के दौरान हड़ताल पर जाने को देश को फिरौती के लिए मजबूर करने और तिरस्कृत करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। न ही उन्हें एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अपने आर्थिक संकट और दुर्दशा को दूर करने के प्रयास के लिए निजी लाभ चाहने वालों के रूप में निंदा की जा सकती है। और इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि श्रमिकों द्वारा देशव्यापी आम हड़ताल हो तो किसी भी श्रमिक के मामले में जांच करना "उचित रूप से व्यावहारिक" नहीं है। अनुच्छेद 311(2)(बी) निश्चित रूप से सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए श्रमिकों की मांगों के समर्थन में बुलाई गई हड़ताल को 'ब्रेक' करने में सक्षम बनाने के लिए संस्थापक पिताओं द्वारा डिजाइन नहीं किया गया था। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य के आलोक में इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए और समीक्षा याचिकाएं स्वीकार की जानी चाहिए।

6. इन आधारों पर और समीक्षा याचिकाओं में आग्रह किए गए अन्य आधारों के आलोक में, समीक्षा याचिकाएं न्यायालय में सुनवाई के योग्य

हैं। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि समीक्षा याचिकाएं स्वीकार की जाएं, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए और मामलों को आगे की सुनवाई के लिए अदालत में रखा जाए।

ए.पी.जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।